

आचार्य श्री विद्यासागर जी की सद्प्रेरणा - धागे से आत्मनिर्भरता का उपक्रम

जबलपुर में 100%
हस्त निर्मित वस्त्रों के
विक्रय केंद्र श्रमदान
अपनापन का भव्य
शुभारंभ 27 मई को



जबलपुर (विश्व परिवार) ।

27 मई 2025, प्रातः 9 बजे, चू मालि, ज्योति टांकोजी के समेत, आनंद होटल, जबलपुर में श्रमदान अपनापन हथकरवा विक्रय केंद्र का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। यह केंद्र पूर्ण आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के वावन आशीर्वाद से प्रारंभ किया जा रहा है। श्रमदान के माध्यम से आज 1500 ग्रामीण परिवारों एवं 450 बर्दियों को एक नया जीवन, सम्मानजनक आजीविका और आत्मनिर्भरता

का अवसर मिला है। यह तक की आय प्राप्त कर रहे हैं। पहल केवल वक्र विक्रय केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक पुनर्निर्माण, पर्यावारीय संतुलन और पुनर्वास की एक मिसाल है।

यह अभिनव अभियान मध्यप्रदेश की 6 जेलों सहित तिहाड़ जेल (दिल्ली), सागर सेंट्रल जेल, बनास सेंट्रल जेल, मिर्जपुर, आगरा एवं मधुरा जेल में संचालित है। इस जेल, मिर्जपुर, आगरा एवं मधुरा जेल में संचालित है, जहाँ बंदी हथकरवा चला कर उपस्थित रहेंगी।

कलेक्टर सूरजपुर जयवर्धन ने की बाल विवाह रोकने की अपील

सूरजपुर ब्लूरो (विश्व परिवार) सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत जनपद पंचायत प्रतापपुर के ग्राम दुकुड़ी में समाधान शिविर का आयोजन कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत उपाध्यक्ष श्री अजीत शरण सिंह, ग्राम सरपंच तथा अन्य जनप्रतिनिधियों भी उपस्थित थे। शिविर के दौरान कुल 13 ग्रामीणों को राशन कार्ड तथा 21 हितग्राहियों को ऋग्या पुस्तिका का वितरण किया गया। साथ ही नशा मुक्ति एवं जल संरक्षण हेतु सामूहिक शपथ दिलाई गई।

कचरा प्रबंधन एवं बाल विवाह पर कलेक्टर को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री विवाह जयवर्धन ने ग्रामपालियों से आग्रह किया कि कचरा प्रबंधन की प्रणाली



को अपनाकर अपने ग्राम को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। उन्होंने कलेक्टर के बाल विवाह के विरुद्ध परायारियों को निर्देशित किया कि जागरूकता फैलाने की अपील करते हुए कहा कि ल ? कियों का विवाह 18 वर्ष और ल ? कों का विवाह 21 वर्ष की आयु से पहले न किया जा। ऐसा न करने से परिवार की वर्तमान और अनेक निवासी के तथा समस्याओं का निराकरण करते तथा मुख्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहें, जिनता की समस्याओं का निवासी के तथा मुख्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहें, जिनता की समस्याओं का निवासी के जानकारी अमाजन की उपलब्ध कराएं। साथ ही नामांतरण, शरीरिक, मानसिक जैसी

धानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित



अधिकृत अनंतलाइन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल में आवेदन कर सकते हैं भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक एवं पात्र युवा निर्धारित अवधि तक

अधिकृत अनंतलाइन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल में आवेदन कर सकते हैं भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल- अवार्ड्स डॉट जीओडी डॉट इन के जरिए स्वीकार किए जाएं।

छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा जीओडी डॉट इन के जरिए स्वीकार किए जाएं।

छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण का आयोजन 6 जून से शानदार ट्राफी का किया गया अनावरण, 6 टीमें लेगीं हिस्सा

रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग (सी.सी.पी.एल.) के प्रथम संस्करण का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व सराहना प्राप्त हुई एवं जिसके फलस्वरूप राज्य के क्रिकेट खिलाड़ीयों को राष्ट्रीय स्तर पर हालात प्राप्त हुई। इंडियन प्रीमियर लीग के गत अॉक्यून में प्रदेश के 7 खिलाड़ीयों को सम्मिलित किया जाना इस सफलता को दर्शाता है।

छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ द्वारा जीओडी डॉट इन के जरिए जीओडी डॉट एल. के दूसरे संस्करण का

आयोजन दिनांक 06 जून 2025 से 15 जून 2025 तक शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नवा रायपुर में किया जाना है। गत वर्ष की भाँती इस वर्ष भी लीग में 6 टीमें हिस्सा लेंगी जिनमें गत वर्ष की विजेता रायपुर रायोन, लालिता सिंह/शांख सिंह, अनिमा सिंह/लाल बहादुर, अनिता/उदय कुमार, फुलेश्वरी/रामलाल, धुनी देवी टेकाम/देववाल सिंह और मोहनी/रामप्रीत शामिल हैं। वहाँ साथ ही नशा राजीव/विजेन्द्र पुरोहित, जन विष्णु विश्व के तथा मनराम नशा के दुष्प्रियाणीमें उद्घासन एवं सतत जीवनशैली के लिए प्रेरित करना था।



राज्य की गरीबा, प्रगती तथा दृढ़ता को प्रदर्शित करता है।

साथ ही सभी 6 टीम तथा उनके कानूनी नींद से जगी है इससे पूर्व खनिज विभाग कुंभकरणी निद्रा में सो रही थी। बता दे की बरसात में ऐसे भी रेत मकिया क्योंतो इतनी जलाने के लिए होते हैं, और इस दिशा में अवैध रेत खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर

में आयोजित किसी भी प्रतियोगिता में यह प्रथम बार होगा।

सोनी टॉप एवं निर्माण के सभी मैवें का सीधा प्रसारण सोनी स्पॉट्स चैनल पर किया जायेगा, जिसके द्वारा खनिज विभाग स्तर पर अनेक देशों में लिए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग (सी.सी.पी.एल.) के दूसरे संस्करण के स्तर को उच्चरण करते हुए इस वर्ष निम्न सुविधाओं के विस्तार करने के लिए आयोजित करना था।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अन्य खिलाड़ीयों को जीतने की उम्मीद है। इस वर्ष निम्न सुविधाओं के विस्तार करने के लिए इस दिन जीवनशैली के लिए एवं अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर

पर गठित टास्क फोर्स द्वारा जीतनी की जा रही है।

प्रशासन एवं निर्माण की नींद से जगी है इससे पूर्व खनिज विभाग कुंभकरणी निद्रा में सो रही थी। बता दे की बरसात में ऐसे भी रेत मकिया क्योंतो इतनी जलाने के लिए होते हैं, और अब अनाक खनिज विभाग का जगना लोगों को औपचारिकता मात्र ही लग रही है।

गैरतलब है कि कलेक्टर जयवर्धन के नेतृत्व में लिये जाएंगे। अवैध रेत खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर

पर गठित टास्क फोर्स द्वारा जीतनी की जा रही है।

गैरतलब है कि बरसात अनेक जगना लोगों को औपचारिकता मात्र ही लग रही है।

गैरतलब है कि बरसात अनेक जगना लोगों को औपचारिकता मात्र ही लग रही है।

गैरतलब है कि बरसात अनेक जगना लोगों को औपचारिकता मात्र ही लग रही है।

गैरतलब है कि बरसात अनेक जगना लोगों को औपचारिकता मात्र ही लग रही है।

गैरतलब है कि बरसात अनेक जगना लोगों को औपचारिकता मात्र ही लग रही है।

गैरतलब है कि बरसात अनेक जगना लोगों को औपचारिकता मात्र ही लग रही है।

गैरतलब है कि बरसात अनेक जगना लोगों को औपचारिकता मात्र ही लग रही है।

गैरतलब है कि बरसात अनेक जगना लोगों को औपचारिकता मात्र ही लग रही है।

दमोह जन परिषद चैप्टर के स्थापना दिवस समारोह में

दुर्वई की इंटरनेशनल मॉडल विद्या जोरी 18 जून को आएंगी



दमोह (विश्व परिवार)। बी ग्रूपिक इंटरनेशनल मिसेज दुर्वई, मोस्टर पॉपुलर फेसऑफ आबू धारी, लोकप्रिय रेनवे मॉडल एवं एडवेसेस सुश्री विद्या जोरी पराह जन परिषद के दमोह चैप्टर के स्थापना दर्शनारोह में बत्तीं मुख्य अधिकारी आगामी 18 जून को दमोह पथरेगे।

दमोह चैप्टर के पदाधिकारी संवैधीर विद्यार्थी, मनोज जैन पत्रकार, दिनेश व्यापी, अधिकारीक संवैधी एडवेसेक, सौरभ विद्यार्थी एवं विद्यार्थी चैप्टर के विशेष व्यापी विद्यार्थी आगामी 18 जून को दमोह पथरेगे।

दमोह

का

कार्यक्रम संपन्न होगा।

उक्त आय

आतंक को संरक्षण नहीं

आतंक को संरक्षण नहीं

भाजपा दश भर में 'तिरंगा यात्रा' नकाल रहा है। इस दारा-भाजपा कार्यकर्ता ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बताएंगे वे क्या बोलेंगे, यानी उनके टॉकिंग प्लाइंट्स क्या होंगे, उसका संकेत प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में दिया। सत्ता पक्ष को शायद अहसास है कि बीते 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, जब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कथानक उसके साथ से फिल्म गया है। ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में अचानक हुए युद्धविराम पर उससे ऐसे हलकों से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, जो आम तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सत्ताधारी समूह के नजरिए से इत्तेफ़ाक रखते हैं। संभवतः इसी अहसास का नतीजा है कि अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन का कार्यक्रम बना और साथ ही खबर आई कि 13 से 23 मई तक भारतीय जनता पार्टी देश भर में 'तिरंगा यात्रा' निकालेगी। इस यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ता लोगों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बताएंगे। वे क्या बोलेंगे, उसका संकेत प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दिया। बल्कि ये कहा जा सकता है कि उन्होंने 'तिरंगा यात्रा' में जाने वाले कार्यकर्ताओं को टॉकिंग प्लाइंट्स दिए। सार यही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के सीने पर वार किया गया और वहां आतंक के ढाँचे को नष्ट कर दिया गया है। इससे घबराए पाकिस्तान ने (डीजीएमओ के जरिए) जब भारत से संपर्क किया और वाद किया कि आगे वहां आतंक को संरक्षण नहीं दिया जाएगा, तब युद्धविराम के जरिए भारत ने पाकिस्तान को एक मौका दिया है मगर ये बातें गले नहीं उतरतीं, क्योंकि दस मई के बाद से उठे कई अहम सवालों के जवाब प्रधानमंत्री के भाषण से नहीं मिले मसलन, युद्धविराम कराने में अमेरिका की क्या भूमिका रही, क्या भारत तटस्थ स्थल पर पाकिस्तान से बातचीत के लिए राजी हुआ है, क्या साढ़े तीन तीन की कार्रवाई के दौरान भारत को लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ, और इस पूरे प्रकरण में- चाहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो या आईएमएफ बोर्ड- भारत दुनिया में अकेला खड़ा क्यों नजर आया? प्रधानमंत्री ने कहा कि टेरर और टॉक साथ-साथ नहीं हो सकते, लेकिन लगे हाथ यह संकेत भी दिया कि भारत पाकिस्तान से आतंकवाद और पीओके के सवाल पर वार्ता के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर प्रश्न अनुत्तरित रहे नैरेटिव का क्या होगा, यह अलग सवाल है।

आलेख

भारत से हज यात्रियों का डिजिटल सशक्तिकरण

सी.पी.एस बर्खी

भारत सरकार ने हाल के वर्षों में समावेशी शासन पर अत्यधिक बल दिया है। एक ऐसा शासन, जो भूगोल, पृष्ठभूमि या विश्वास की परवाह किए बिना हर नागरिक तक पहुंचता हो। यह बात वार्षिक हज यात्रा के संचालन में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एक नियमित प्रशासनिक क्रियाकलाप से दूर, यह एक विशाल मानवीय, कूटनीतिक और तार्किक संचालन है, जो अनेक राष्ट्रों और संस्कृतियों तक फैला हुआ है। सबका साथ, सबका विकास के लोकाचार से प्रेरित होकर सरकार ने हज प्रबंधन को 21वीं सदी की सेवा वितरण के माडल के रूप में परिणत कर दिया है। भारत से हर साल लगभग 1.75 लाख तीर्थयात्री पवित्र हज यात्रा पर जाते हैं। सऊदी अरब समाप्त्य (केएसए) के साथ घनिष्ठ समन्वय में, भारतीय हज समिति के माध्यम से चार महीने तक चलने वाले इतने व्यापक और संवेदनशील ऑपरेशन का प्रबंधन करना राष्ट्रीय समन्वय, कूटनीति और सेवा का एक महत्वपूर्ण नमूना है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि यह आध्यात्मिक यात्रा निर्बाध होने के साथ-साथ गरिमापूर्ण, समावेशी और तकनीकी रूप से सशक्त भी हो। बिना किसी पक्षपात के सभी समुदायों की सेवा करने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ, सरकार हज के अनुभव को विदेशों में अब तक किए गए सबसे उत्तम सार्वजनिक सेवा संचालन में से एक के रूप में परिणत कर रही है। हज सुविधा ऐप को भारत सरकार ने 2024 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य तीर्थयात्रियों के अनुभव को सरल और बेहतर बनाना था। इसके माध्यम से प्रत्येक तीर्थयात्री से जुड़े राज्य हज निरीक्षकों के विवरण के साथ-साथ निकटतम स्वास्थ्य सेवा और परिवहन सुविधाओं सहित आवास, परिवहन और उड़ान संबंधी विवरण जैसी सूचनाओं तक तकाल पहुंच कायम करना संभव हो रहा है। यह ऐप शिकायत प्रस्तुत करने, उसकी ट्रैकिंग करने, बैगेज ट्रैकिंग, आपातकालीन एसओएस सुविधाएं, आध्यात्मिक सामग्री और तत्काल सूचनाएं प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। पिछले साल 67,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने ऐप इंस्टॉल किया था, जो स्वीकृति की उच्च दर का संकेत देता है। केएसए में भारत सरकार द्वारा हाजियों के

लिए स्थापित प्रशासनिक ढांचे द्वारा 8000 से अधिक शिकायतें और 2000 से अधिक एसओएस उठाए गए और उनका जवाब दिया गया। ऐप की फीडबैक-संचालित डिजाइन तीर्थयात्रा की पूरी अवधि के दौरान निरंतर सुधार की सुविधा देती है। हज-2024 के दौरान ऐप से प्राप्त जानकारी ने 2025 के लिए हज नीति और दिशानिर्देश तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में काम किया। ये डेटा-समर्थित निर्णय भारत सरकार के अपने नागरिकों के लिए उत्तरदायी शासन के मॉडल का उदाहरण हैं। 2024 में इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए, सरकार ने अब हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च किया है। यह हज के पूरे दायरे को कवर करता है और तीर्थयात्रियों के लिए वास्तव में एंड-टू-एंड डिजिटल समाधान तैयार करता है। हज 2.0 में हज यात्रियों के डिजिटल आवेदन, चयन (कुर्रा), प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन, भुगतान एकीकरण, अदाही कूपन जारी करने और रद्दीकरण तथा धन वापसी की प्रक्रियाओं से लेकर हज की पूरी प्रक्रिया शामिल है। अपेंट किया गया ऐप बैंकिंग नेटवर्क के साथ सहज एकीकरण प्रदान करता है, जिससे तीर्थयात्री यूपीआई, डेबिट/क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। यात्रा के दौरान सुविधा के लिए तत्काल उड़ान संबंधी सूची और इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास भी प्रदान किए जाते हैं। ऐप को पेडोमीटर सुविधा के साथ संवर्धित किया गया है। इसका उद्देश्य तीर्थयात्रियों में पैदल चलने की आदत डालना है, ताकि उनमें आगे की कठिन यात्रा के लिए आवश्यक सहनशक्ति विकसित हो सके। तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए तत्काल मौसम के अपेंट भी जोड़े गए हैं, ताकि तीर्थयात्रियों को जलवायु संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में मदद मिल सके और साथ ही उन्हें स्वस्थ और हाइड्रेटेड रखा जा सके। भारतीय हज चिकित्सा दल को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और यह मकाएवं मदीना में हज के दौरान स्थापित क्षेत्रीय अस्पतालों तथा औषधालयों के नेटवर्क के माध्यम से तीर्थयात्रियों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। एम्बुलेंस का एक नेटवर्क आपतकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करता है।

रिश्वत लेकर सवाल पूछने का नेताओं काला इतिहास रहा है

योगेंद्र योगी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा का मामला अभी भी देश के लोगों की स्मृति से मिटा भी नहीं है। महुआ मोइत्रा ने रियल एस्टेट कारोबारी दर्शन हीरानंदनी के व्यवसायिक हितों की रक्षा के लिए संसद में सवाल पूछे। देश के नेताओं ने आजादी के बाद से भ्रष्टाचार के इतने काले कारनामे किए हैं कि यदि कोई नेता ईमानदारी से अच्छा भी काम करे तब भी उस पर सहज भरोसा करना मुश्किल होता है। देश के लोगों की याद से नेताओं के काले कारनामे की छाप मिटे, इससे पहले ही कोई न कोई नया कांड ऐसा सामने आता है और पूरे तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। नया मामला राजस्थान का है। भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के एक विधायक जयकृष्ण पटेल को राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने विधानसभा में सवाल पूछने के बदले 20 लाख रुपए की रिश्त लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान की इस क्षेत्रीय पार्टी के दो विधायक और एक सांसद हैं। आदिवासियों के उत्थान के आहवान के साथ इस पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कुल चार सीटें जीती, तीन सीटें राजस्थान में और एक सीट मध्यप्रदेश में जीती। बीएपी की टिकट पर दूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय सीट जीतने वाले राजकुमार रोत लोकसभा से सांसद बने। रिश्त लेने के आरोपी बीएपी विधायक पटेल ने विधानसभा में बीते सत्र के दौरान 11 जुलाई 2024 को अवैध खनन, फर्म हाउस, वन्य जीव और नशा तस्करी को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कुछ सवाल किये गए थे। विधानसभा में इन्हीं खनन से जुड़े सवालों को हटवाने को लेकर रिश्त का खेल शुरू हुआ। बीएपी विधायक ने इन सवालों को हटाने के लिए 10 करोड़ की डिमांड की थी। अंततः 20 लाख में सौदा तय हुआ और विधायक पटेल को रंगे हाथों दबोच लिया गया। यह पहला मौका नहीं है जब किसी जनप्रतिनिधि ने सदन की पवित्रता को तार-तार किया है। इससे पहले भी मामले सामने आ चुके हैं, जब विधानसभा हो या लोकसभा में सवाल पूछने या नहीं पूछने के ऐवज में रिश्त मांग कर समूचे लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया गया है।

प्रभा साक्षी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा का मामला अभी भी देश के लोगों की स्मृति से मिटा भी नहीं है। महुआ मोइत्रा ने रियल एस्टेट कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के व्यवसायिक हितों की रक्षा के लिए संसद में सवाल पूछे। आरोप था कि महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी के इशारे पर 61 सवालों में 50 में अंबानी और अडानी को टारगेट किया। दर्शन हीरानंदानी ने खुलासा किया कि महुआ मोइत्रा ने अपनी संसद लॉगिन और पासवर्ड उनके साथ साझा किया था। उन्होंने महुआ की ओर से सवाल पोस्ट किए थे। एथिक्स कमेटी ने 6-4 के बहुमत से महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म करने की सिफरिश कर दी। टीएमसी सांसद मोइत्रा से पहले भी जनप्रतिनिधियों के ऐसे कृत्यों से देश में राजनीतिक बवंडर उठ चुके हैं। वर्ष 2005 में ऐसे ही एक अन्य मामले में लोकसभा के 10 और राज्यसभा के एक सांसद की सदस्यता रद्द हुई थी। तब एक वेब पोर्टल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। स्टिंग में 11 सांसद सवाल के बदले में कैश का ऑफर स्वीकार करते दिखे थे। इनमें लोकसभा के 10 और राज्यसभा के 1 सदस्य को निष्कासित कर दिया गया था। तब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए-1 की सरकार थी। संसद की सदस्यता गंवाने वालों में 6 बीजेपी के थे, 3 बीएसपी के और 1-1

कांग्रेस के सांसद थे। स्टिंग में सबसे कम कैश 15000 रुपये की भाजपा सांसद छत्रपाल सिंह लोढ़ के सामने पेशकश की गई थी जबकि सबसे ज्यादा कैश 1,10,000 रुपये आरजेडी के सांसद मनोज कुमार को ऑफर की गई थी। 24 दिसंबर 2005 के संसद में वोटिंग के जरिए आरोपी सभी 11 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया। लोकसभा में प्रणब मुखर्जी ने 10 सांसदों के निष्कासन का प्रस्ताव रखा था जबकि राज्यसभा में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने एक सांसद को निष्कासित करने का प्रस्ताव रखा था। वोटिंग के दौरान भाजपा बॉकआउट कर गई थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन नेत प्रतिपक्ष एल्के आडवाणी ने कहा था कि सांसदों ने जो कुछ किया वह करप्तान कम, मूर्खता ज्यादा है इसके लिए निष्कासन बहुत ही कठोर सजा होगी जनवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सांसदों के निष्कासन के फैसले को सही ठहराया था। उसी साल दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज किया था। न्यूज पोर्टल के देव पत्रकारों के खिलाफी चार्जशीट दाखिल हुई। संसद राज्यसभा हो या लोकसभा, सदन में सत्र की कार्यवाही के दौरान असहज कर देने वाली घटनाओं का पुराना इतिहास रहा है। पहले भी ऐसी कई घटनाओं का गवाह बना है जाहे वो पैसे के लेन-देन को लेकर आरोप लगाने का मामला हो या फिर नोटों

काशी, अयोध्या की तर्ज होगा बृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का विकास
मंदिर ट्रस्ट के धन का होगा इस्तेमाल, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला.....

अजय दाक्षत

(धर्मक्षेत्र)

आगामी कुछ दिनों बाद श्रद्धालुओं को बृद्धावन में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए संघर्ष नहीं करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की एक याचिका पर सुनवाई कर मंदिर की आसपास की पांच एकड़ भूमि को अधिग्रहण करने की स्वीकृति दी है और साथ में 500 करोड़ रुपए मंदिर ट्रस्ट से खर्च करने की घोषणा को भी सही ठहराया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अलाहाबाद हाइकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील की थी जिसमें कहा गया था कि पांच एकड़ भूमि के विकास के लिए मंदिर बृद्धावन ट्रस्ट के धन का उपयोग नहीं किया जाए। जनसंख्या दबाव के कारण भारत के प्रमुख मंदिर अव्यवस्था से जूझ रहे हैं जिनमें बृद्धावन का सुप्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर भी हैं। बताया जाता है कि भगवान् श्री कृष्ण की इस प्रतिष्ठित मूर्ति की प्राचीन काल में संत हरिदास महाराज ने स्थापित किया था। कहते हैं कि ये 1600 ईसवी के आसपास की बात है। तत्कालीन समय में एक मंदिर भी बनाया गया था जो यमुना नदी के किनारे था तब यहां सघन बन हुआ करता था और उसमें बृंदा के पेड़ थे तो बृद्धावन प्रचलित हो गया। संत हरिदास महाराज भगवान् श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और वह बन में मथुरा में कुछ बस्ती थी। एक भगवान् श्री कृष्ण की जन्मभूमि थी जो लगभग महाभारत काल की ही थी। लेकिन समय के साथ बृद्धावन में परिवर्तन हुआ। ब्रिटिश काल में 1884 में मंदिर का नए सिरे से निर्माण हुआ। 1970 तक यहां मंदिरों की स्थली ही थी जैसे पागल बाबा का मंदिर, द्वारिका धीश मंदिर आदि। वर्तमान समय में बृद्धावन एक तीर्थ स्थलों में से एक है यहां पूरे भारत से श्रद्धालुओं का आना जाना होता है। एक पर्यटक स्थल बन गया है बल्कि एक सर्किट बन गया है जिसमें गोकुल, दाऊजी, मथुरा, गोवर्धन, बरसाना शामिल हैं लगभग सौ किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गई है। एक अनुमान के मुताबिक मथुरा पूरे देश से पांच करोड़ लोगों द्वारा प्रतिवर्ष दर्शन करने आते हैं। इस लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय हारित प्राधिकरण के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर मथुरा और आसपास के क्षेत्रों को नवीनतम प्रारूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने केएनबीजी,(कोसी, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन) सड़क परिवहन निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, मथुरा से डींग बाया गोवर्धन, तथा गोवर्धन सोख, गोकुल, सड़क परियोजना भी 1000 करोड़ की स्वीकृत की

है। दिल्ली, आगरा, भरतपुर, से शनिवार को 5000 वाहन आते हैं और अब बृद्धावन की पुलिस अधिकारियों के चुनौती बन गई है ट्रैफिक व्यवस्था बांके बिहारी मंदिर के पास कुंज गालियां, उनमें बस्तियां हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की समिति की सिफारिश पर यह फैसले लिया है कि मंदिर बृद्धावन ट्रस्ट के चारों ओर हरित क्षेत्र बनाया जाए और पूरी बस्ती का पुनर्वास करने अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से उत्तर प्रदेश सरकार अब एक कोरिडोर का निर्माण कार्य शुरू कर सकती है जिसमें पर्यटकों के सुविधा मिल सके। हरित क्षेत्र में पेड़े को उगाया जाए, हरियाली रहे। भगवान् श्री कृष्ण और राधा रानी का दिव्य स्थान बने। भारत सरकार में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसीन हुए हैं तब से कार्शन विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या में भगवान् श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर बने हैं। मैंने कई दक्षिण भारत के मंदिरों के दर्शन किए हैं, जैसे मदुरई, रामेश्वरम, महाबलिपुरम, जगन्नाथपुरी, कोच्चि, त्रिचनपल्ली, पद्मानाभ मंदिर, द्वारिका, सर्वानंद अभी भी व्यवस्थित हैं जबकि उत्तर भारत के मंदिरों में अव्यवस्था हैचाहे वह केदारनाथ, ब्रदीनाथ गंगोत्री, यमनोत्री, कैला देवी, हो एक भगवान् श्री कृष्ण की जन्मभूमि थी जो लगभग महाभारत काल की ही थी। लेकिन समय के साथ बृद्धावन में

परिवतन हुआ। ब्रिटिश काल में 1884 में मंदिर का नए सिरे से निर्माण हुआ। 1970 तक यहां मंदिरों की स्थली ही थी जैसे पागल बाबा का मंदिर, द्वारिका धीश मंदिर आदि। वर्तमान समय में बृंदावन एक तीर्थ स्थलों में से एक है यहां पूरे भारत से श्रद्धालुओं का आना जाना होता है। एक पर्यटक स्थल बन गया है बल्कि एक सर्किट बन गया है जिसमें गोकुल, दाऊजी, मथुरा, गोवर्धन, बरसाना शामिल हैं लगभग सौ किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गई है। एक अनुमान के मुताबिक मथुरा पूरे देश से पांच करोड़ लोगों प्रतिवर्ष दर्शन करने आते हैं। आजादी के 77 वर्ष बाद ये कार्य शुरू हो रहे हैं जबकि विश्व में भारत ही ऐसा देश है जिसमें सनातन धर्म के मंदिर हैं नेपाल में यद्यपि पशुपतिनाथ मंदिर है। मगर व्यवस्था वहां भी ठीक नहीं है। वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन कांग्रेस सरकार रहते हिन्दुओं के तीर्थ स्थलों पर कोई कार्य नहीं किया गया। जबकि भारत में 80 फीसदी से अधिक आवादी हिंदुओं की है। बताया जाता है कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार प्रथम राष्ट्रपति स्व राजेंद्र प्रसाद ने कराया था। लेकिन स्व जवाहर लाल नेहरू राजेंद्रजी के इस निर्णय से सहमत नहीं थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि हे इस एक्सीडेंटल हिन्दू। नेहरू नहीं चाहते थे कि डॉ राजेंद्र प्रसाद, सर्वोच्च पद पर रहते किसी मंदिर का पुनर्वास कराए।

ऑपरेशन सिंदूर से बदली नीतियों का वैश्विक संकेत

અન્દા વારુપદા

ऑपरेशन सिंदूर के तहत चली महज चार दिनों की कार्रवाई के बाद संघर्ष विराम होने को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा है। बड़े वर्ग का मानना है कि पाकिस्तानी उकसावे के बाद जारी भारतीय कार्रवाई से पाकिस्तान की गर्दन भारतीय पैरों के नीचे आ गई थी। बीती छह मई की देर रात को पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर गरजती मिसाइलों ने दुनिया को कई संदेश दिए हैं। भारतीय कार्रवाई का पहला संदेश यह है कि अब ना सिर्फ भारत, बल्कि उसकी विदेश नीति भी बदल चुकी है। अब अगर भारत का बेगुनाह खुन बहेगा तो खून बहाने वाले नापाक हाथों को भारत कहीं से भी ढूँढ़ निकालेगा और उसकी कब्र खोदेन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तानी हमले के सफल प्रतिकार ने स्वदेशी हथियार तकनीक की खुद-ब-खुद ब्राइंडिंग हो गई। पहलगाम के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद भारतीय राजनीति और राजनय को देखने का दुनिया का नजरिया बदलना तय है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत चली महज चार दिनों की कार्रवाई के बाद संघर्ष विराम होने को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा है। बड़े वर्ग का मानना है कि पाकिस्तानी उकसावे के बाद जारी भारतीय कार्रवाई से पाकिस्तान की गर्दन भारतीय

पैरों के नीचे आ गई थी। लिहाजा जस्ती था कि उसकी कमर तोड़ दी जाए। भारत के एक बड़े वर्ग को उम्मीद थी कि मौजूदा कार्रवाई के जरिए पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। बहुत लोगों तो लगता था कि अगर ऑपरेशन सिंटूर जारी रहता तो बलूचिस्तान के लिए पाकिस्तान से अलग होने की राह आसान हो जाती। इस लिहाज देखें तो भारत का लोकमानस पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के पक्ष में था या कह सकते हैं कि अब भी है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि युद्ध कभी-भी जनमत के दबाव में लड़े जाते। आधुनिक दौर में जब लड़ाई और हथियारों में तकनीक की पहुंच और पैठ बढ़ी है, सिफर्जनमत के दबाव में युद्ध लड़ना ताकतवर से ताकतवर देश के लिए संभव नहीं। इस बीच संघर्ष विराम पर राष्ट्रपति ट्रूप के उतावले दावों ने संघर्ष विराम की हकीकत की जिज्ञासा बढ़ा दी है। लोग यह जानने के लिए उतावले हैं कि संघर्ष विराम की असल बजह आखिर क्या है? वैसे ऐसी संवेदनशील जानकारियां शायद ही कभी बाहर आ पाती हैं। इसलिए संघर्ष विराम के पीछे की असलियत को आने वाला इतिहास ही जान पाएगा। जिस तरह पाकिस्तान के एयरबेस समेत तमाम सैनिक ठिकानों को भारतीय सेना ने निशाना बनाया है, उससे बिलबिलाकर वह



अमेरिका को शरण में पहुंचा और युद्ध विराम कराने के लिए गुहार लगाने लगा। यह जानकारी कुछ अमेरिकी अखबारों के पत्रों पर आ चुकी है। बहरहाल ऑपरेशन सिंटूर ने संदेश दिया है कि अब भारत रणनीति के तहत जवाब नहीं देगा, बल्कि अपने नागरिकों पर हमले, संभ्रुता और अखंडता पर चोट की हालत में वह निर्णायक कार्रवाई करेगा। इस ऑपरेशन ने एक लक्षण रेखा खींच दी है, जिसे नजरंदाज करना पाकिस्तान के लिए अब संभव नहीं होगा। उसे अब पता चल गया है कि राजनीति और सेना पोषित आतंकवाद और आतंक की नीति को सीधा और करारा जवाब मिलेगा। भारत पिछले करीब साढ़े चार दशक से आतंकवाद को झेल रहा है। पाकिस्तान पहले पंजाब को आतंकवादी आग से झुलसाता रहा तो वह के दिनों में जमू-कश्मीर में खून बहाने रहा। पाक परस्त आतंकी अगर भारतीय संसद, वाराणसी, जयपुर, मुंबई आंगाहों पर बेगुनाह खून बहाने में कामयार हो तो इसकी बड़ी वजह रही पाकिस्तान व आतंकवाद केंद्रित नीति। ऑपरेशन सिंटूर के जारी भारत ने संदेश दिया है कि अब यह नीति नहीं चलेगी। इस बात आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों व जिस तरह भारत ने सफल निशाना बनाया उसके बाद अब आतंकी कार्रवाई करने पहले सौ बार सोचने को मजबूर होंगे। अउहें सोचना होगा कि आतंक फैलाकर दूसरे देश की सीमा में जाकर चैन से न रह पाएंगे। भारत की सेना उहें उनके घर ही मारेगी। ऑपरेशन सिंटूर पर संघर्ष

विराम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में दो-तीन बड़ी बातें कहीं पहला यह कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा। यानी सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि टेरर यानी आतंक और ट्रेड यानी कारोबार एक साथ नहीं चलेगा। यानी आतंक फैलाने वाले देशों के साथ भारत ना तो कारोबार करेगा और न ही उन्हें कोई विशेष दर्जा देगा सवाल यह है कि भारत की इस बदली नीति की वजह क्या है? भारत की इस बदली नीति की वजह है, उसकी बढ़ती आर्थिक ताकत। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिहाज से भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। जल्द ही जापान की अर्थव्यवस्था को वह पीछे छोड़ देगा। भारत की स्वदेशी हथियार तकनीक, चाहे आकाश प्रिसाइल हो या रूस के सहयोग से विकसित ब्रह्मोस, उन्होंने अपनी अनुकूल मारक क्षमता दिखाई दी है। एक तरफ देश आर्थिक ताकत बढ़ाता जा रहा है तो दूसरी ओर तरफ सैनिक ताकत भी बढ़ रही है। शारीर के लिए मजबूत आर्थिक और सैनिक ताकत जरूरी होती है। कहना न होगा कि आर्थिक और सामरिक ताकत की वजह से भारत अपनी नीति बदलता हुआ दिख रहा है भारत की अब तक की घोषित नीति रही है कि वह किसी दूसरे देश के मामले में न हस्तक्षेप करेगा।

